भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2962

(जिसका उत्तर सोमवार, 07 अगस्त, 2023/16 श्रावण, 1945 (शक) को दिया गया)

फिनटेक स्टार्ट-अप

2962. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डीः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू फिनटेक स्टार्ट-अप वित्तपोषण में वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में 47 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ख) सरकार द्वारा घरेलू फिनटेक स्टार्ट-अप वित्तपोषण को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने की संभावना है;
(ग) वर्ष 2019 से शुरू हुए और बंद किए गए फिनटेक स्टार्ट-अप की राज्य/वार-वर्ष-वार संख्या कितनी है; और
(घ) गत तीन वर्षों के दौरान स्टार्ट-अप्स के बंद हो जाने के कारण राज्य/वर्ष-वार कितने कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख): उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, देश के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, सरकार ने 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की। 19 फरवरी 2019 की सा.का.नि. अधिसूचना 127 (अ) के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत संस्थाओं को 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यता दी गई है। 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल के शुभारंभ के बाद से, डीपीआईआईटी ने 30 अप्रैल 2023 तक 98,119 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी है। इसके अतिरिक्त,

डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप को मान्यता दी है जो 56 से अधिक विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। 30 अप्रैल 2023 तक, 3,085 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप वित्त प्रौद्योगिकी (फिनटेक) क्षेत्र में लगे हुए हैं।

सरकार ने फिनटेक क्षेत्र में लगे स्टार्टअप्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं। ऐसी पहलों का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में वित्तीय सेवाओं, वित्तीय संस्थानों और वित्तीय उत्पादों को विकसित करने और विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को अधिसूचित किया है। विशेष रूप से फिनटेक क्षेत्र में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए, आईएफएससीए ने विभिन्न उपाय जैसे - फिनटेक और टेकफिन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अद्वितीय 'फिन-टेक एंटिटी फ्रेमवर्क' लॉन्च किए हैं। यह ढांचा स्टार्टअप को आईएफएससीए के नवाचार और नियामक सैंडबॉक्स के तहत अपने उत्पादों/न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमवीपी) को विकसित करने या 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) करने के लिए सहायता प्रदान करता है। आईएफएससीए ने फिनटेक और स्टार्टअप्स के लिए एक प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है जिसमें स्टार्टअप अनुदान, सैंडबॉक्स अनुदान, पीओसी अनुदान, ग्रीन फिनटेक अनुदान, लिस्टिंग अनुदान और त्वरक अनुदान जैसे विभिन्न अनुदान शामिल हैं। फिनटेक स्टार्टअप को वैश्विक बाजार पहुंच के लिए आईएफएससीए द्वारा अन्य अंतर्राष्ट्रीय नियामकों के साथ बनाए गए 'नियामक सेतु' से भी लाभ होता है।

सरकार ने फिनटेक क्षेत्र में निवेश प्रवाह बढ़ाने के लिए भी कई उपाय किए हैं। प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और कई वित्तीय सेवाओं के अनुप्रयोगों तक पहुंच के लिए लाभार्थियों के नए बैंक खाता नामांकन में मदद करके भारत में वित्तीय समावेशन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसने फिनटेक स्टार्टअप को भारत में बड़े उपभोक्ता आधार में प्रवेश करने के लिए प्रौद्योगिकी उत्पादों का निर्माण करने में सक्षम बनाया है।

आधार, अद्वितीय बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली, जनता को सरकारी डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देती है, जिससे जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता सहित सामाजिक भुगतान के लिए उपलब्धता और पारदर्शिता में सुधार होता है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एकल मंच है जो विभिन्न बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं को एक छत्र-छाया के नीचे विलय करता है और इसे भारत में डिजिटल भुगतान का समर्थन करने वाले स्केलेबल भुगतान मंच के रूप में बनाया गया है।

एकीकृत भुगतान इंटरफेस के साथ जन धन योजना, आधार और मोबाइल (जेएएम ट्रिनिटी) तकनीकी समावेशन प्रदान करने और पारदर्शिता, अखंडता और जनता को वित्तीय लाभ और सेवाओं के समय पर वितरण में सहायक रहे हैं। भारत में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों को अनुलग्नक-II में रखा गया है। घरेलू फिनटेक स्टार्टअप वित्तपोषण के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पास कोई आंकडे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पास कोई आंकडे उपलब्ध नहीं हैं।

******

लोकसभा के दिनांक 07.08.2023 के अतारांकित पश्न संख्या 2962 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

देश भर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:

1. स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान: स्टार्टअप इंडिया के लिए एक कार्य योजना का अनावरण 16 जनवरी 2016 को किया गया था। कार्य योजना में "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन" और "उद्योग-शिक्षा साझेदारी और इनक्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों में फैले 19 कार्य मद शामिल हैं। कार्य योजना ने देश में एक जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए परिकल्पित सरकारी सहायता, योजनाओं और प्रोत्साहनों की नींव रखी।

2. स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) योजना: सरकार ने स्टार्टअप की फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ एफएफएस की स्थापना की है। डीपीआईआईटी निगरानी एजेंसी है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) एफएफएस के लिए परिचालन एजेंसी है। योजना की प्रगति और धन की उपलब्धता के आधार पर 14 वें और 15 वें वित्त आयोग चक्रों में 10,000 करोड़ रुपये की कुल निधि प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इसने न केवल स्टार्टअप्स के लिए शुरूआती अवस्था, बीजीय अवस्था और विकास अवस्था में पूंजी उपलब्ध कराई है, बल्कि घरेलू पूंजी जुटाने की सुविधा, विदेशी पूंजी पर निर्भरता को कम करने और घरेलू और नए उद्यम पूंजी फंडों को प्रोत्साहित करने के मामले में उत्प्रेरक भूमिका निभाई है।

3. स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस): सरकार ने सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और उद्यम ऋण निधियों (वीडीएफ) द्वारा डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की स्थापना की है। सीजीएसएस का उद्देश्य सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा पात्र उधारकर्ताओं जैसे डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के वित्तपोषण के लिए दिए गए ऋणों के खिलाफ एक निर्दिष्ट सीमा तक क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है।

4. नियामक सुधार: सरकार द्वारा 2016 से व्यापार करने में आसानी, पूंजी जुटाने में आसानी और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के लिए 50 से अधिक नियामक सुधार किए गए हैं।

5. खरीद में आसानी: खरीद में आसानी को सक्षम करने के लिए, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने के अधीन सभी डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए सार्वजनिक खरीद में पूर्व कारोबार और पूर्व अनुभव की शर्तों में ढील देने का निर्देश दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) स्टार्टअप रनवे विकसित किया गया है जो स्टार्टअप्स के लिए उत्पादों और सेवाओं को सीधे सरकार को बेचने के लिए एक समर्पित कॉर्नर है।

6. बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए समर्थन: स्टार्टअप फास्ट-ट्रैक पेटेंट आवेदन परीक्षा और निपटान के लिए पात्र हैं। सरकार ने स्टार्ट-अप बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) आरंभ किया है जो स्टार्टअप को केवल वैधानिक शुल्क का

भुगतान करके उपयुक्त आईपी कार्यालयों में पंजीकृत सुविधाप्रदाताओं के माध्यम से पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के लिए आवेदन फाइल करने की सुविधा प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत सुविधा प्रदाता विभिन्न आईपीआर पर सामान्य सलाह प्रदान करने और अन्य देशों में आईपीआर की सुरक्षा और संवर्धन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। सरकार किसी भी पेटेंट, ट्रेडमार्क या डिजाइन के लिए सुविधाप्रदाताओं की पूरी फीस वहन करती है, और स्टार्टअप केवल देय वैधानिक शुल्क की लागत वहन करते हैं। स्टार्टअप्स को पेटेंट फाइल करने में 80% छूट और अन्य कंपनियों की तुलना में ट्रेडमार्क भरने में 50% छूट प्रदान की जाती है।

7. श्रम और पर्यावरण कानूनों के तहत स्व-प्रमाणन: स्टार्टअप को निगमन की तारीख से 3 से 5 साल की अवधि के लिए 9 श्रम और 3 पर्यावरण कानूनों के तहत अपने अनुपालन को स्व-प्रमाणित करने की अनुमति है।

8. 3 साल के लिए आयकर छूट: 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद गठित स्टार्टअप आयकर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को इंटरमिनिस्ट्रियल बोर्ड सर्टिफिकेट दिया जाता है, उन्हें निगमन के बाद से 10 वर्षों में से लगातार 3 वर्षों की अवधि के लिए आयकर से छूट दी जाती है।

9. भारतीय स्टार्टअप के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंच: स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत प्रमुख उद्देश्यों में से एक विभिन्न जुड़ाव मॉडल के माध्यम से भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने में मदद करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय सरकार से सरकार की साझेदारी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भागीदारी और वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी के माध्यम से किया गया है। स्टार्टअप इंडिया ने 17 से अधिक देशों के साथ ब्रिज लॉन्च किए हैं जो भागीदार देशों के स्टार्टअप के लिए सॉफ्ट-लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और क्रॉस सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता करता है।

10. स्टार्टअप्स के लिए फास्टर एग्जिट : सरकार ने स्टार्टअप्स को 'फास्ट ट्रैक फर्मों' के रूप में अधिसूचित किया है, जिससे वे अन्य कंपनियों के लिए 180 दिनों की तुलना में 90 दिनों के भीतर परिचालन बंद कर सकते हैं।

11. स्टार्टअप इंडिया हब: सरकार ने 19 जून 2017 को एक स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब लॉन्च किया, जो भारत में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारकों के लिए एक-दूसरे के साथ खोजने, जुड़ने और संलग्न करने के लिए अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन हब स्टार्टअप, निवेशक, फंड, मेंटर्स, अकादमिक संस्थान, इनक्यूबेटर, एक्सेलेरेटर, कारपोरेट्स, सरकारी निकायों और इत्यादि के लिए आयोजन करता है।

12. अधिनियम (2019) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (VII) (ख) के उद्देश्य के लिए छूट: एक डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (viiख) के प्रावधानों से छूट के लिए पात्र है।

13. स्टार्टअप इंडिया शोकेस: स्टार्टअप इंडिया शोकेस वर्चुअल प्रोफाइल के रूप में प्रदर्शित स्टार्टअप के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चुने गए देश के सबसे होनहार स्टार्टअप के लिए एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। मंच पर प्रदर्शित स्टार्टअप अपने क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ के रूप में उभरे हैं। ये नवाचार फिनटेक, एंटरप्राइजटेक, सोशल इम्पैक्ट, हेल्थटेक, एडटेक जैसे विभिन्न अत्याधुनिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ये स्टार्टअप महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान कर

रहे हैं और अपने संबंधित क्षेत्रों में असाधारण नवाचार प्रदर्शित किया है। पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों ने इन स्टार्टअप का पोषण और समर्थन किया है, जिससे इस मंच पर उनकी उपस्थिति को मान्य किया गया है।

14. राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद: सरकार ने जनवरी 2020 में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के गठन को अधिसूचित किया ताकि सतत आर्थिक विकास को चलाने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए देश में नवाचार और स्टार्टअप को पोषित करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह दी जा सके। पदेन सदस्यों के अतिरिक्त, परिषद में कई गैर-आधिकारिक सदस्य हैं, जो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

15. स्टार्टअप इंडिया: आगे का रास्ता: स्टार्टअप इंडिया: स्टार्टअप इंडिया के 5 साल पूरे होने के उत्सव में आगे का रास्ता 16 जनवरी 2021 को अनावरण किया गया था, जिसमें स्टार्टअप के लिए व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने, विभिन्न सुधारों को निष्पादित करने में प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका, हितधारकों की क्षमताओं का निर्माण और डिजिटल आत्मनिर्भर भारत को सक्षम करने के लिए कार्रवाई योग्य योजनाएं शामिल हैं।

16. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस): उद्यम के विकास के शुरुआती चरणों में उद्यमियों के लिए पूंजी की आसान उपलब्धता आवश्यक है। इस स्तर पर आवश्यक पूंजी अक्सर अच्छे व्यावसायिक विचारों वाले स्टार्टअप के लिए मेक-या-ब्रेक की स्थिति प्रस्तुत करती है। इस योजना का उद्देश्य अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यावसायीकरण के प्रमाण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2021-22 से शुरू होने वाले 4 वर्षों की अवधि के लिए एसआईएसएफएस योजना के तहत 945 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

17. राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (एनएसए): राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार उन उत्कृष्ट स्टार्टअप और पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने वालों को पहचानने और पुरस्कृत करने की एक पहल है जो रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता के साथ अभिनव उत्पादों या समाधानों और स्केलेबल उद्यमों का निर्माण कर रहे हैं, जो औसत दर्जे के सामाजिक प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। सभी फाइनलिस्टों को विभिन्न ट्रैकों जैसे निवेशक कनेक्ट, मेंटरशिप, कारपोरेट साथ को, गवर्नमेंट संपर्क, इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस, नियामक सहायता, दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैंपियंस और स्टार्टअप इंडिया शोकेस आदि में हैंडहोल्डिंग सपोर्ट प्रदान किया जाता है।

18. राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क (एसआरएफ): राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क प्रतिस्पर्धी संघवाद की ताकत का उपयोग करने और देश में एक समृद्ध स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक अनूठी पहल है। रैंकिंग अभ्यास के प्रमुख उद्देश्य राज्यों को अच्छी प्रथाओं की पहचान करने, सीखने और बदलने की सुविधा प्रदान करना, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप को उजागर करना है।

19. दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैंपियन: दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैंपियंस कार्यक्रम एक घंटे का साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसमें पुरस्कार विजेता/राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के वृतांत शामिल हैं। यह दूरदर्शन नेटवर्क चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रसारित किया जाता है।

20. स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक: सरकार राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अर्थात् 16 जनवरी के आसपास स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन करती है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य देश के प्रमुख स्टार्टअप, उद्यमियों, निवेशकों, इनक्यूबेटरों, फंडिंग संस्थाओं, बैंकों, नीति निर्माताओं और अन्य राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को उद्यमिता का उत्सव मनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाना था।

21. स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल को सिडबी के साथ स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सह-विकसित किया गया है, जो एक मध्यस्थ मंच के रूप में कार्य करता है जो विभिन्न उद्योगों, कार्यों, चरणों, क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के उद्यमियों को पूंजी जुटाने में मदद करने के लिए स्टार्टअप और निवेशकों को जोड़ता है। पोर्टल विशेष रूप से सक्षम करने के उद्देश्य से बनाया गया है; देश में कहीं भी स्थित शुरुआती चरण के स्टार्टअप प्रमुख निवेशकों/वेंचर कैपिटल फंडों के सामने खुद को प्रदर्शित करने के लिए। वर्तमान में, 82 वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) और 1,900 से अधिक स्टार्टअप पहले ही प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हो चुके हैं।

22. नेशनल मेंटरशिप पोर्टल (एमएएआरजी): देश के हर हिस्से में स्टार्टअप्स के लिए मेंटरशिप तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलिएंस एंड ग्रोथ (एमएएआरजी) कार्यक्रम विकसित और लॉन्च किया गया है।

23. एसेंड: एसेंड (स्टार्टअप कैलिबर और एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव में तेजी) के तहत, सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्टार्टअप और उद्यमिता पर संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिसका उद्देश्य उद्यमिता के प्रमुख पहलुओं पर ज्ञान को बढ़ाना और बढ़ाना और इन राज्यों में एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में प्रयास जारी रखना है।

24. स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप: स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत के विश्वास के परिणामस्वरूप, भारत के जी 20 प्रेसीडेंसी के तहत एक स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप को संस्थागत रूप दिया गया है जो सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच सामंजस्य और क्रॉस सहयोग की दिशा में काम कर रहा है। एंगेजमेंट ग्रुप वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की आवाज के रूप में कार्य करता है जो विभिन्न हितधारकों को एक आम मंच पर लाता है। समूह का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप, कारपोरेट्स, निवेशकों, नवाचार एजेंसियों और अन्य प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों के बीच तालमेल को सक्षम करके और वैश्विक तालमेल बनाकर स्टार्टअप का समर्थन करना है।

****

<u>लोकसभा के दिनांक 07.08.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2962 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक</u>

अनुलग्नक-II

<u>भारत में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल निम्नानुसार हैं:</u>

1. जन धन योजना का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और वित्तीय सेवाओं के आवेदनों की एक मेजबानी तक पहुंच के लिए लाभार्थियों के नए बैंक खाता नामांकन में मदद करके भारत में वित्तीय समावेशन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसने फिनटेक स्टार्टअप को भारत में बड़े उपभोक्ता आधार में प्रवेश करने के लिए प्रौद्योगिकी उत्पादों का निर्माण करने में सक्षम बनाया है।

2. इंडिया स्टैक एक सामाजिक पहल है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी डिजिटल पहलों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, जिसमें वित्त में प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाना शामिल है।

3. आधार, विशिष्ठ बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली, ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली और आधार भुगतान सेतु प्रणाली की सुविधा दी है:

- **आधार सक्षम भुगतान प्रणाली** व्यक्तियों को अपना आधार नंबर प्रस्तुत करके और अपने फिंगरप्रिंट / आईरिस स्कैन की मदद से इसे सत्यापित करके माइक्रो-एटीएम पर वित्तीय लेनदेन करने की अनुमति देती है।
- **आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम** बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके आधार से जुड़े बैंक खातों से संचालन की सुविधा प्रदान करते हुए थोक और आवर्ती सरकारी लाभ और सब्सिडी भुगतान में आसानी की सुविधा देता है।

4. डिजिटल केवाईसी, वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया और दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर सहित प्रमाणीकरण समाधानों के विकास और रोल-आउट ने फिनटेक स्टार्टअप और ग्राहकों के लिए इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी-सक्षम समाधानों का लाभ उठाने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय और परेशानी मुक्त प्रणाली बनाई है।

- विभिन्न वित्तीय संस्थानों के लिए कई केवाईसी से गुजरने की परेशानी को कम करने के लिए एक केंद्रीय भंडार, सेंट्रल केवाईसी विकसित किया गया है। यह उपभोक्ताओं की

केवाईसी प्रक्रिया को केवल एक बार आयोजित करने की अनुमति देता है जब तक कि उपभोक्ता विवरण में कोई बदलाव न हो।

- **केवाईसी और ग्राहक ऑनबोर्डिंग लागत में** काफी कमी आई है, जिससे ग्रामीण भारत में वित्तीय सेवाओं का विस्तार हो रहा है और उनके खाते खुल रहे हैं।

5. **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस** को भारत में डिजिटल भुगतान का समर्थन करने वाले स्केलेबल भुगतान मंच के रूप में बनाया गया है।
6. **भुगतान बैंकों के लिए लाइसेंस** ने भुगतान बैंकों की स्थापना की अनुमति देकर और भुगतान/ प्रेषण सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके देश में वित्तीय समावेशन अभियान को बढ़ाने में मदद की है। देश में डिजिटल भुगतान बैंकों को बढ़ावा देने के लिए, आरबीआई ने भुगतान बैंकों के लिए दिन के अधिकतम शेष राशि को 2 लाख रुपये तक बढ़ाने की घोषणा की है।
7. **थोक लेनदेन करने के लिए नेशनल ऑटोमेडिट क्लियरिंग हाउस सिस्टम** का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है।
8. **भारत बिल भुगतान प्रणाली** ने उपयोगिताओं और अन्य क्षेत्रों में बिलों का भुगतान करने के लिए उपभोक्ता सुविधा को बढ़ाने में मदद की है और स्वैच्छिक रूप से पात्र प्रतिभागियों के रूप में आवर्ती बिल (प्रीपेड रिचार्ज को छोड़कर) उठाने वाले बिलर्स की सभी श्रेणियों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया है।
9. भारतीय रिजर्व बैंक ने टियर-3 से टियर-6 केंद्रों में भुगतान स्वीकृति अवसंरचना अवसंरचना की तैनाती को सब्सिडी देने के लिए एक **भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ)** योजना भी विकसित की है।
10. **भारतीय रिजर्व बैंक ने पी2पी उधारदाताओं को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में मान्यता देकर पीयर-टू-पीयर (**पी2पी) उधार के आसपास एक नियामक ढांचा बनाया है, इस प्रकार बैंक रहित लोगों को वैकल्पिक ऋण पहुंच प्रदान की गई है।
11. **आईआरडीएआई** ने बीमा सम्यक को बढ़ाने की दिशा में विभिन्न पहल की हैं, जैसे कि बीमा कंपनियों को वीडियो-आधारित केवाईसी करने की अनुमति देना, मानकीकृत बीमा उत्पादों को

लॉन्च करना और बीमा कंपनियों को कम जोखिम वाले व्यवहार के लिए पुरस्कार प्रदान करने की अनुमति देना।

- **स्वास्थ्य** मंत्रालय और नीति आयोग जैसे सरकारी संस्थान भी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम), स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (दिशा) में डिजिटल सूचना सुरक्षा अधिनियम (दिशा) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टैक के माध्यम से **बीमा उद्योग में परिवर्तन का समर्थन** कर रहे हैं।

12. भारत को वैश्विक फिनटेक हब बनाने के दृष्टिकोण को और मजबूत करने के लिए गांधीनगर, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी), **गिफ्ट सिटी** में एक विश्व स्तरीय **फिनटेक हब** विकसित किया गया है।

****